DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

26 October, 2023

जापान-भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी

सन्दर्भ: हाल ही में कैबिनेट ने तकनीकी सहयोग और सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत-जापान सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को मंजूरी दे दी है।

- जापान-भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी के लिए MoC; भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय साझेदार है।
- एमओसी का मुख्य उद्देश्य उद्योगों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के लिए इसके महत्व को पहचानते हुए सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को आगे बढ़ाने में सहयोग को मजबूत करना है।
- एमओसी हस्ताक्षर करने के साथ ही प्रभावी हो जाता है और पांच वर्ष के लिए वैध होता है।
- यह सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने और पूरक शक्तियों का लाभ उठाने के लिए सरकार-से-सरकार (जी2जी) और बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) सहयोग को प्रोत्साहित करता है।
- इस समझौते में बढ़ते सहयोग के परिणामस्वरूप आईटी क्षेत्र में संभावित रोजगार के अवसरों की भी परिकल्पना की गई है।
- डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (डीआईसी) के तहत भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम विकास को संचालित करता है।

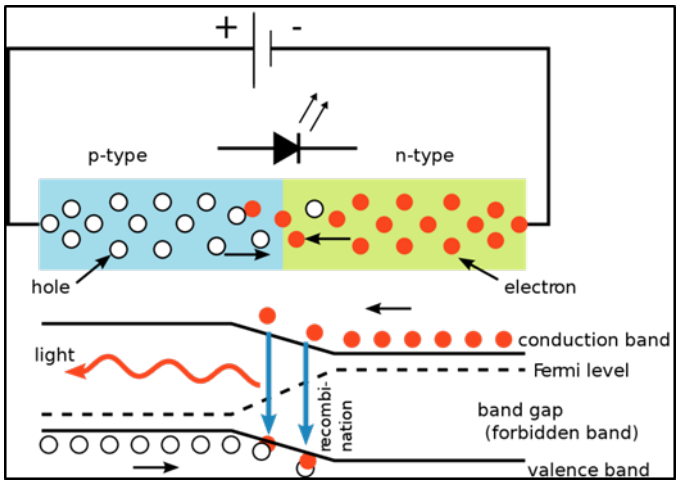

भारत सेमीकंडक्टर मिशन:

- ISM (इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन) की शुरुआत वर्ष 2021 में 76,000 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय आवंटन के साथ की गई थी, यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत संचालित होता है।
- यह भारत के भीतर एक स्थायी अर्धचालक और प्रदर्शन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए एक व्यापक रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है।
- इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले विनिर्माण और डिजाइन क्षेत्रों में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- आईएसएम को सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उद्योगों में वैश्विक विशेषज्ञों के नेतृत्व में डिज़ाइन किया गया है, जो योजनाओं के कुशल और सुसंगत कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

आईएसएम के प्रमुख घटक:

- **सेमीकंडक्टर फैब्स (Fabs) योजना**: यह योजना पर्याप्त निवेश आकर्षित करते हुए सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **डिस्प्ले फैब्स योजना: यह** महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करने के लिए टीएफटी एलसीडी और AMOLED डिस्प्ले विनिर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर फैब, और सेमीकंडक्टर एटीएमपी/ओएसएटी योजना:** कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर (एमईएमएस सहित), और सेमीकंडक्टर असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग से संबंधित सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता के रूप में पूंजीगत व्यय का 30% अनुदान देती है।
- **डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) योजना:** आईसी, चिपसेट, एसओसी, सिस्टम और आईपी कोर सहित सेमीकंडक्टर डिजाइन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और डिजाइन समर्थन प्रदान करती है।

सेमी कंडक्टर (अर्धचालक)

- अर्धचालक आमतौर पर सिलिकॉन जैसी सामग्री से बना होता है।
- यह इंसुलेटर (जैसे, कांच) से बेहतर बिजली का संचालन करता है, लेकिन शुद्ध कंडक्टर (जैसे, तांबा या एल्यूमीनियम) जितना अच्छा नहीं।
- सेमीकंडक्टर AI, IoT, 5G संचार, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- इसके अनुप्रयोगों में बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और कारों से लेकर रणनीतिक संचालन सभी शामिल हैं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी)

सन्दर्भ:: हाल ही में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने उत्तराखंड के लिए जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को पीएमकेएसवाई-एआईबीपी में शामिल किया।

- पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत परियोजना के शेष कार्य घटकों के लिए 90:10 अनुपात (केंद्र: राज्य) में केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस परियोजना को मार्च 2028 तक पूरा किया जाना है।
- इससे उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के रामपुर और बरेली जिलों में अतिरिक्त 57 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचाई के दायरे में आ जाएगी।
- यह परियोजना हलद्वानी और आसपास के क्षेत्रों में 42.70 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) पीने के पानी की आपूर्ति भी करेगी, जिससे 10.65 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे।
- 14 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ लगभग 63.4 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन की उम्मीद है।

पीएमकेएसवाई

- इसे 2015 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया।
- केंद्र और राज्यों के बीच फंडिंग आवंटन 75:25 है, पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों को छोड़कर इसका वित्त पोषण भाग 90:10 है।

उद्देश्य:

- क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश के अभिसरण को सुविधाजनक बनाना।
- सुनिश्चित सिंचाई (हर खेत को पानी) के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना।
- पानी की बर्बादी को कम करने के लिए खेत में पानी के उपयोग की दक्षता बढ़ाना।
- परिशुद्धता-सिंचाई और अन्य जल-बचत प्रौद्योगिकियों (प्रति बूंद अधिक फसल) को अपनाने को बढ़ावा देना।
- जलभृतों के पुनर्भरण और टिकाऊ जल संरक्षण प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित करना।
- परिनगरीय कृषि के लिए उपचारित नगरपालिका अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग करने की व्यवहार्यता का पता लगाना।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

- सटीक सिंचाई प्रणालियों में अधिक निजी निवेश आकर्षित करना।
- पीएमकेएसवाई को कई चालू योजनाओं को मिलाकर तैयार किया गया है, जिसमें शामिल हैं:
  - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के तहत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)।
  - ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के तहत एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)।
  - कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी) के तहत ऑन-फार्म जल प्रबंधन (ओएफडब्ल्यूएम)।
  - पीएमकेएसवाई का कार्यान्वयन विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से किया जाता है, जिसमें राज्य सिंचाई योजनाएं और जिला सिंचाई योजनाएं शामिल हैं।

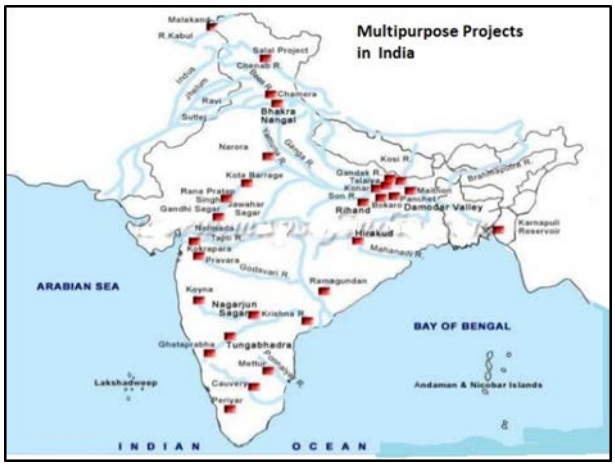

भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाएँ:

- **बिजली उत्पादन:** वे उद्योग और कृषि के लिए स्वच्छ, कम लागत वाली बिजली प्रदान करते हैं
- **बाढ़ नियंत्रण:** ये परियोजनाएँ पानी का भंडारण करती हैं, बाढ़ को रोकती हैं और नियंत्रित करती हैं।
- **मृदा संरक्षण:** जल प्रवाह को धीमा करके, वे मिट्टी के संरक्षण में सहायता करते हैं।
- **सिंचाई:** बहुउद्देशीय परियोजनाएँ नहरों के माध्यम से शुष्क मौसम में सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति करती हैं।
- **वनरोपण:** वन्य जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करते हुए जलाशयों के पास पेड़ लगाए जाते हैं।
- **जल नेविगेशन:** वे भारी माल के लिए लागत प्रभावी अंतर्देशीय जल परिवहन का समर्थन करते हैं।
- **मत्स्य पालन:** मछली प्रजनन के लिए आदर्श स्थितियाँ बनाई जाती हैं।
- **पर्यटक आकर्षण:** इन परियोजनाओं को लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित और रखरखाव किया जाता है।

निवारक निरोध (Preventive Detention)

सन्दर्भ: हाल ही में तेलंगाना सरकार के निवारक निरोध कानून के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में प्रश्न उठाए हैं।

निवारक निरोध क्या है?

- निवारक निरोध में राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर, बिना मुकदमे या बिना अदालती दोषसिद्धि के, एक वर्ष तक के लिए हिरासत में रखा जाता है, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है।
- यह प्री-ट्रायल डिटेंशन से अलग है, जो अपराधों के आरोपी विचाराधीन व्यक्तियों पर लागू होता है।
- ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में, निवारक निरोध का उपयोग मुख्य रूप से युद्ध के दौरान किया जाता है।
- भारत में, मौलिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देने के बावजूद, संविधान भाग III के अंतर्गत अनुच्छेद 22 के तहत निवारक निरोध की अनुमति देता है।

किन कानूनों के तहत हिरासत में लिया जा सकता है?

- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और COFEPOSA (विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974) संघीय कानून हैं जो निवारक निरोध की अनुमति देते हैं।
- इसके अलावा, 25 भारतीय राज्यों ने अपने स्वयं के निवारक निरोध कानून स्थापित किए हैं; प्रत्येक को विशिष्ट स्थानीय कानून और व्यवस्था संबंधी चिंताओं को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- उदाहरण के लिए, तेलंगाना में डकैतों, ड्रग-अपराधियों, गुंडों, अनैतिक व्यापार अपराधियों, भूमि-कब्जा करने वालों, कीटनाशक अपराधियों, उर्वरक अपराधियों, खाद्य अपमिश्रण अपराधियों, नकली दस्तावेज़ अपराधियों, अनुसूचित की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम वस्तु अपराधी, वन अपराधी, गेमिंग अपराधी, यौन अपराधी, विस्फोटक पदार्थ अपराधी, हथियार अपराधी, साइबर अपराध अपराधी, और सफेदपोश या वित्तीय अपराधी अधिनियम, 1986 (पीडी अधिनियम) लागू है।
- तमिलनाडु जैसे अन्य राज्यों ने ड्रग अपराधियों, वन अपराधियों, गुंडा, अनैतिक तस्करी अपराधियों और स्लम ग्रैबर्स अधिनियम, 1982 की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम जैसे समान कानून बनाए हैं।
- इसके अतिरिक्त, गुजरात में असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1985 लागू है।
- अन्य बातों के अलावा बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 का उपयोग करता है।

अनुच्छेद 22 और निवारक निरोध

- संविधान में अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है लेकिन निवारक निरोध कानूनों के तहत हिरासत में लिए गए लोगों के लिए एक अपवाद (अनुच्छेद 22(3)(बी)) है।
- निवारक निरोध कानून राज्य को, आमतौर पर जिला मजिस्ट्रेट को, "सार्वजनिक व्यवस्था" बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की अनुमति देते हैं और यह शक्ति पुलिस को सौंपी जा सकती है।
- यदि हिरासत तीन महीने से अधिक समय के लिए है, तो अनुच्छेद 22(4) एक सलाहकार बोर्ड की मंजूरी को अनिवार्य करता है। इन बोर्डों में आमतौर पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश और नौकरशाह शामिल होते हैं, और हिरासत में लिए गए व्यक्ति का बोर्ड के समक्ष कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है।
- यदि सलाहकार बोर्ड निरोध की पुष्टि करता है, तो बंदी हिरासत आदेश को अदालत में चुनौती दे सकता है।
- अनुच्छेद 22(5) के तहत राज्य को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तुरंत निरोध के आधार के बारे में सूचित करने और उन्हें आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का जल्द से जल्द अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है।
- निरोध के आधार को सूचित किया जाना चाहिए, और राज्य मूल निरोध आदेश को मजबूत करने के लिए नए आधार पेश नहीं कर सकता है। इस आधार को बंदी द्वारा समझी जाने वाली भाषा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- हालाँकि, अनुच्छेद 22(6) राज्य को उन तथ्यों का खुलासा नहीं करने की अनुमति देता है जिन्हें वह "सार्वजनिक हित के विरुद्ध" मानता है, जो अनुच्छेद 22(5) में प्रदान किए गए सुरक्षा को आंशिक रूप से कमजोर कर सकता है।

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

26 October, 2023

NEWS IN BETWEEN THE LINES

जमरानी बांध परियोजना

हाल ही में, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने उत्तराखंड के नैनीताल जिले में जमरानी बांध परियोजना के लिए ₹1,557.18 करोड़ की केंद्रीय सहायता की स्वीकृति प्रदान की है।

जमरानी बांध परियोजना के बारे में:

- इस परियोजना में जमरानी गांव के पास एक बांध का निर्माण शामिल है, जो नैनीताल में राम गंगा की सहायक गोला नदी पर स्थित होगा।
- यह बांध मौजूदा गोला बैराज को उसकी नहरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करेगा।
- 150.6 मीटर की ऊंचाई वाले जमरानी बांध का निर्माण गोला नदी पर करने की योजना है।
- इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) में शामिल किया गया है।
- जमरानी बांध परियोजना को वर्ष 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
- इस बांध परियोजना से सालाना 63 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न होने की सम्भावना है।

ह्यूमन राइट्स वॉच

हाल ही में, ह्यूमन राइट्स वॉच ने इज़राइल पर गाजा में सफेद फास्फोरस हथियारों का उपयोग करने का आरोप लगाया, जिससे नागरिकों की सुरक्षा का दीर्घकालिक खतरा उत्पन्न हो गया है।

ह्यूमन राइट्स वॉच के बारे में:

- यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है जो मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करता है। यह न्यूयॉर्क शहर में स्थित है और दुनिया भर में इसके 100 से अधिक कार्यालय हैं।
- हेलसिंकी समझौते के साथ सोवियत संघ के अनुपालन की निगरानी के लिए ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) की स्थापना 1978 में "हेलसिंकी वॉच" के रूप में की गई थी।
- 1988 में इसका विस्तार होकर ह्यूमन राइट्स वॉच बन गया।
- इसने बारूदी सुरंगों पर प्रतिबंध लगाने के अंतर्राष्ट्रीय अभियान के संस्थापक सदस्य के रूप में 1997 में नोबेल शांति पुरस्कार साझा किया।
- इसने क्लस्टर युद्ध सामग्री पर प्रतिबंध लगाने वाली 2008 की संधि में अग्रणी भूमिका निभाई।
- यह शरणार्थियों, बच्चों, प्रवासियों और राजनीतिक कैदियों के अधिकरों का समर्थन करता है।
- यह मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) के अनुसार बुनियादी मानव अधिकारों के उल्लंघन का विरोध करता है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

हाल ही में, 116 सदस्य देशों वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) ने नवंबर में पहली **'वैश्विक सौर स्टॉक-टेक रिपोर्ट'** संकलित करने और जारी करने की घोषणा की।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में:

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) एक अंतरसरकारी संगठन है जिसे 30 नवंबर 2015 को स्थापित किया गया था।
- इसकी स्थापना भारत के प्रधान मंत्री (नरेंद्र मोदी) और फ्रांस के राष्ट्रपति (फ्रांस्वा ओलांद) ने पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में की थी।
- इसका लक्ष्य 1000 गीगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना और सालाना 1000 मिलियन टन CO_2 को कम करना है।

दृष्टि और लक्ष्य:

- **दृष्टि:** "आइए हम सब मिलकर सूर्य को उज्जवल बनाएं।"
- **मिशन:** "हर घर, चाहे वह कितना भी दूर क्यों न हो, घर में रोशनी होगी।"
- **मुख्यालय:** गुरूग्राम, भारत

क्यूबिज्म

क्यूबिज़्म (Cubism) के बारे में:

- क्यूबिज्म एक प्रभावशाली कला आंदोलन था जो 1907 में शुरू हुआ था, जिसकी विशेषता वस्तुओं को एक साथ कई दृष्टिकोणों से चित्रित करना था।
- इस आंदोलन का नेतृत्व **स्पेनिश कलाकार पाब्लो पिकासो और फ्रांसीसी चित्रकार जॉर्ज ब्रैक** ने किया था।
- क्यूबिज्म ने प्रकृति की प्रत्यक्ष प्रति के रूप में कला के पारंपरिक दृष्टिकोण को खारिज कर दिया, इसके बजाय वस्तुओं के द्वि-आयामी प्रतिनिधित्व और विखंडन पर जोर दिया।
- क्यूबिज्म में कलाकारों का लक्ष्य त्रि-आयामीता के भ्रम से दूर जाकर, एक सपाट कैनवास पर किसी वस्तु के विभिन्न पक्षों और पहलुओं को दिखाना था।
- क्यूबिज़्म 1900 के दशक की शुरुआत की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से प्रभावित था, जो परमाणु और पदार्थ के परस्पर संबंधित टुकड़ों की एक नई समझ को दर्शाता है।
- क्यूबिज्म का कला जगत पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने बाद के आंदोलनों और कलाकारों को प्रभावित किया और आधुनिक कला के विकास में योगदान दिया।

शि यान 6

हाल ही में श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि चीनी अनुसंधान पोत शि यान 6 (Shi Yan 6) कोलंबो बंदरगाह पर पहुंच गया है।

शी यान 6 के बारे में:

- शि यान 6 एक चीनी अनुसंधान और सर्वेक्षण पोत है।
- यह चीनी समुद्र विज्ञान सर्वेक्षण जहाजों की एक श्रृंखला से संबंधित है।
- जहाज की वहन क्षमता 1115 DWT (डेडवेट टनेज) है।
- इसमें 60 व्यक्ति सवार हैं।

सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: मुख्य रूप से भारत द्वारा उठाई गई सुरक्षा चिंताओं के कारण श्रीलंका ने जहाज के आगमन की अनुमति देने में देरी की।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

गाइडेड मिसाइल पनडुब्बियां

पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में चीन ने अपनी पहली परमाणु संचालित गाइडेड मिसाइल पनडुब्बियां लॉन्च की हैं।

गाइडेड मिसाइल पनडुब्बियों के बारे में:

- एसएसजीएन (शिप सबमर्सिबल गाइडेड मिसाइल न्यूक्लियर) के नाम से जानी जाने वाली ये पनडुब्बियां चीन को जमीन और समुद्री हमले के विकल्प रखने में सक्षम बनाती हैं जो ऐतिहासिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के पास ही थे।
- एसएसजीएन को मूल रूप से शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ द्वारा क्रूज मिसाइलों, लंबी दूरी के, सटीक-निर्देशित हथियारों के साथ विमान वाहक को लक्षित करने के लिए विकसित किया गया था। यह समुद्र की सतह के करीब सबसोनिक गति से उड़ते हैं।
- क्रूज़ मिसाइलों की कम ऊंचाई वाली उड़ान प्रोफ़ाइल उन्हें रडार द्वारा पता लगाने से बचने में सक्षम बनती हैं, जिससे वे हमले का एक गुप्त और प्रभावी साधन बन जाते हैं।

पेंटागन की रिपोर्ट:

20 अक्टूबर को प्रकाशित पेंटागन की रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि चीनी शिपयार्डों में देखी गई संशोधित पनडुब्बियां टाइप 093बी निर्देशित मिसाइल पनडुब्बियां हैं।

अंटार्कटिका की खोई हुई दुनिया

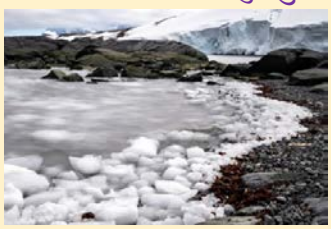

वैज्ञानिकों ने पूर्वी अंटार्कटिका के **विल्क्स लैंड** में एक विशाल प्राचीन परिदृश्य का पता लगाया है, जो आकार में बेल्जियम या अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के बराबर क्षेत्र है।

अंटार्कटिका की खोई हुई दुनिया के बारे में:

- यह परिदृश्य हिंद महासागर के साथ पूर्वी अंटार्कटिका के विल्केस लैंड क्षेत्र में स्थित है, जो लगभग बेल्जियम के आकार के क्षेत्र को कवर करता है।
- यह परिदृश्य अतीत की झलक पेश करता है जब अंटार्कटिका में गर्म जलवायु थी जो पेटागोनिया की वर्तमान जलवायु से लेकर उष्णकटिबंधीय जलवायु के लगभग समान थी।
- प्राचीन परिदृश्य के ऊपर की बर्फ की मोटाई लगभग 2.2-3 किलोमीटर है।
- परिदृश्य का निर्माण विस्तारित भूवैज्ञानिक समयावधि में नदियों, टेक्टोनिक्स और हिमनदी से प्रभावित था।
- लगभग 34 मिलियन वर्ष पहले, अंटार्कटिका की जलवायु तस्मानिया और पैटागोनिया जैसे क्षेत्रों में आधुनिक ठंडे शीतोष्ण वर्षावनों के समान थी।
- प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण अलग होने से पहले अंटार्कटिका कभी गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा था, जिसका बाद में भूवैज्ञानिक अलगाव हो गया।
- **अंटार्कटिका की उपसतह का रहस्य:** मंगल की सतह की तुलना में अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे की भूमि की कम खोज की गई है।

ऐतिहासिक महत्व: यह परिदृश्य कम से कम 14 मिलियन वर्ष पुराना है जो संभवतः 34 मिलियन वर्ष से भी अधिक पुराना है जब अंटार्कटिका गहरी ठंड से गुजरा था

समाचारों में स्थान

लेबनान

हाल ही में लेबनान के हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने हमास और इस्लामिक जिहाद के अधिकारियों के साथ बैठक की।

लेबनान (राजधानी: बेरूत)

अवस्थिति : लेबनान मध्य पूर्व में स्थित है, इसकी सीमा पश्चिम में भूमध्य सागर, पूर्व और उत्तर में सीरिया और दक्षिण में इज़राइल से लगती है।

राजनीतिक सीमाएँ: लेबनान पूर्व और उत्तर में सीरिया से, दक्षिण में इज़राइल से घिरा है।

भौगोलिक विशेषताएं:

- भूमध्यसागरीय तटरेखा एक प्रमुख भौगोलिक विशेषता है।
- माउंट लेबनान और एंटी-लेबनान पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसी **बेका घाटी**, देश की एक महत्वपूर्ण घाटी है।

POINTS TO PONDER

- कितने एशियाई देशों ने ओलंपिक की मेजबानी की है, और किसने 1964 और 2020 में दो बार खेलों की मेजबानी की है? **- तीन,चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। जापान ने दो बार, 1964 और 2020 में, खेलों की मेजबानी की है।**
- भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) एक विशेष बल है। इसका हालिया संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास क्या था? **- सैन्याभ्यास , हरिमौ शक्ति-2023**
- सोमालिया सहित उन दो देशों के नाम बताइए, जिनमें 1976 में चेचक का संक्रमण था, लेकिन फरवरी 1977 तक इसका उन्मूलन हो गया। **- भारत और बांग्लादेश**
- "कस्तूरी कॉटन इंडिया" की ट्रैसेबिलिटी, प्रमाणन और ब्रांडिंग को लागू करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? **- सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद (TEXPROCIL)**
- 2021 और 2022 में किस देश से आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) देशों में सबसे अधिक प्रवास प्रवाह हुआ? **- भारत**